शनिवार

15 अगस्त 2026

● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 203
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

34 साल से देहरादून का विश्वास

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस

❑परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में सीएम ने किया ध्वजारोहण

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड, में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। समारोह का शुभारंभ राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के सामूहिक गायन से हुआ।

आज यहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड, में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। समारोह का शुभारंभ राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के सामूहिक गायन से हुआ। इसके उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन का सामूहिक गायन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया तथा फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 14 पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया। जिसमें 7 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा के आधार पर एवं 6 को विशिष्ट कार्यों के आधार पर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय प्रदर्शन करने वाले 13 खिलाड़ियों को भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन घड़ी में राज्य सरकार

प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रभावित परिवारों तक शीघ्र राहत पहुंचाना, घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना तथा जिन लोगों ने अपने घर एवं आजीविका खोई है, उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक है। इस वर्ष देश स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तथा राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी वर्ष संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती तथा सिक्ख पंथ के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी वर्ष भी मनाया जा रहा है। उन्होंने विभाजन विभीषिका के दौरान अमानवीय यातनाएं झेलने, अपनों को खोने और विस्थापन का दर्द सहने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होने कहा कि देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। बलिदानियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों की अनुग्रह राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की गई है। प्रत्येक बलिदानी परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में समायोजित करने के साथ सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ, शासन के सचिव, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून प्रमेन्द्र डोभाल एवं अन्य महानुभाव उपस्थित थे।

बारिश में 'धंस' रहा उत्तराखंड

❑हाईवे से बाजार और घरों तक मंडराया खतरा, बारिश ने की परीक्षा लेनी शुरू

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। मानसून उत्तराखंड के लिए इस बार सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि पहाड़ की कमजोर होती जमीन का इम्तिहान बनता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में जमीन धंसने और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर ग्रामीण सड़कों तक कहीं सड़क धंस रही है तो कहीं सड़क के नीचे की जमीन खिसक रही है। सबसे बड़ी चिंता उन बाजारों और आबादी वाले क्षेत्रों को लेकर है, जहां पहाड़ी ढलानों पर वर्षों से निर्माण होता आया है। सड़क कटने या जमीन धंसने का असर अब सिर्फ यातायात तक सीमित नहीं रह गया है। कई जगह आसपास बने भवनों की नींव पर भी खतरा मंडराने लगा है।

◆कहीं हाईवे का हिस्सा धंस रहा तो कहीं सड़क के नीचे की जमीन खिसक रही
◆बाजार व आबादी वाले इलाकों पर खतरा बढ़ा, कई जगह भवनों की नींव हिली

बारिश के दौरान पहाड़ी सड़कों पर दरारें पड़ना और सड़क का हिस्सा धंसना नया नहीं है। लेकिन लगातार सामने आ रही घटनाओं ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पहाड़ों में सड़क निर्माण के दौरान भूगर्भीय स्थिति और जल निकासी को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है? जहां सड़क के किनारे पानी की निकासी की व्यवस्था कमजोर है, वहां बारिश का पानी पहाड़ के भीतर पहुंचकर मिट्टी और चट्टानों को कमजोर कर सकता है। इसके बाद ढलान का संतुलन बिगड़ते ही जमीन खिसकने लगती है। कई स्थानों पर सड़क को बचाने के लिए तत्काल डामर या मलबा डाल दिया जाता है। इससे रास्ता कुछ समय के लिए चलने लायक तो हो जाता है, लेकिन यदि मूल समस्या का उपचार नहीं हुआ तो अगली बारिश में वही संकट फिर सामने आ जाता है।

कई जगह जमीन में छोटी दरारें शुरुआत में मामूली दिखाई देती हैं। लेकिन लगातार बारिश के बाद यही दरारें बड़े भूस्खलन का संकेत बन सकती हैं। यही कारण है कि विशेषज्ञ लंबे समय से बारिश के मौसम में संवेदनशील ढलानों और भवनों की निगरानी की जरूरत बताते रहे हैं। हर बार पहाड़ टूटने के बाद सबसे आसान जवाब होता हैकृभारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या बारिश अकेली जिम्मेदार है? प्राकृतिक बारिश को रोका नहीं जा सकता। लेकिन बारिश के पानी को पहाड़ के भीतर जाने से रोकना, जल निकासी व्यवस्था मजबूत करना, संवेदनशील ढलानों की पहचान करना और निर्माण के दौरान भूगर्भीय जोखिम को समझना इंसानी जिम्मेदारी है। अगर हर मानसून में सड़क धंसे और हर बार हम बारिश को दोष देकर आगे बढ़ जाएं तो समस्या का समाधान कब होगा?

उत्तराखंड को सड़कें चाहिए। बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए। पर्यटन और चारधाम यात्रा के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा चाहिए। लेकिन सवाल सड़क बनाने का नहीं, सुरक्षित सड़क बनाने का है। पहाड़ को मैदान की तरह काटकर सड़क बनाना और फिर बारिश आने पर सुरक्षा कार्य शुरू करना दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता। जरूरत है कि संवेदनशील क्षेत्रों का वैज्ञानिक सर्वे हो। सड़क निर्माण से पहले

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

दून वैली मेल

संपादकीय

आजादी का अमृत नहीं, लोकतंत्र की परीक्षा

15 अगस्त 1947 को देश ने सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति नहीं पाई थी, बल्कि एक ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें सत्ता जनता के प्रति जवाबदेह होगी, संविधान हर नागरिक को बराबरी देगा और लोकतंत्र कमजोर की आवाज को भी उतनी ही जगह देगा, जितनी ताकतवर की आवाज को। आज जब भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तब तिरंगे के नीचे खड़े होकर सबसे जरूरी सवाल यही है क्या हम उस सपने के करीब पहुंचे हैं? आजादी के 79 वर्षों में भारत ने लंबी यात्रा तय की है। गरीबी से जूझते देश से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने तक, खाद्यान्न संकट से आत्मनिर्भरता तक, बैलगाड़ी के दौर से डिजिटल इंडिया तक और सीमित संसाधनों से अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक भारत ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। लोकतंत्र ने भी अनेक उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत बनी रहीं। लेकिन उपलब्धियों के इस उत्सव के बीच उन सवालों को भी सुनना होगा जो अक्सर राष्ट्रवाद के शोर में दब जाते हैं। क्या हर युवा को रोजगार मिल रहा है? क्या हर बच्चे को समान शिक्षा मिल रही है? क्या गांव का अस्पताल शहर के अस्पताल का विकल्प बन पाया है? क्या पहाड़ का नागरिक अपने घर में रहकर सम्मानजनक जीवन जी सकता है? क्या किसान अपनी मेहनत की उचित कीमत पा रहा है? क्या आम आदमी महंगाई के दबाव से मुक्त है? और सबसे बड़ा सवाल क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा पहले जैसा मजबूत है? आजादी का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। आजादी का अर्थ भय से मुक्ति भी है। भेदभाव से मुक्ति भी है। भूख और बेरोजगारी से मुक्ति भी है। अन्याय के सामने चुप रहने की मजबूरी से मुक्ति भी है। भारत का संविधान इसी व्यापक स्वतंत्रता का दस्तावेज है। संविधान हमें अधिकार देता है तो सत्ता को मर्यादा भी सिखाता है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस केवल प्रधानमंत्री के भाषण, परेड और राष्ट्रगान का दिन नहीं है। यह आत्ममंथन का दिन भी है। आज राजनीतिक दल एक-दूसरे पर राष्ट्रविरोध, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगाते हैं। आरोपों की इस राजनीति में कहीं नागरिक पीछे छूट जाता है। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव जरूर हैं, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं है। लोकतंत्र संसद में सवाल पूछने, मीडिया के स्वतंत्र रहने, न्यायपालिका की निष्पक्षता, संस्थाओं की विश्वसनीयता और नागरिक की असहमति के सम्मान से मजबूत होता है। असहमति लोकतंत्र की दुश्मन नहीं, उसकी आक्सीजन है। आज जरूरत इस बात की है कि हम राष्ट्रभक्ति को भी संकीर्ण अर्थों से बाहर निकालें। देश से प्रेम केवल नारे लगाने से साबित नहीं होता। सड़क पर गड्ढा देखकर सवाल करना भी देशभक्ति है। सरकारी स्कूल में शिक्षक की कमी पर आवाज उठाना भी देशभक्ति है। भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना भी देशभक्ति है। किसी गरीब के अधिकार के लिए लड़ना भी देशभक्ति है और सत्ता से सवाल पूछना भी देशभक्ति है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए स्वतंत्रता दिवस का अर्थ और भी गहरा है। यहां तिरंगा उन गांवों में भी पहुंचना चाहिए जहां सड़क अभी सपना है, जहां युवा रोजगार के लिए मैदानों की ओर जा रहा है, जहां अस्पताल तक पहुंचने में घंटों लगते हैं और जहां पलायन धीरे-धीरे गांवों की सामाजिक संरचना बदल रहा है। देवभूमि की असली तरक्की केवल बड़े प्रोजेक्टों, चौड़ी सड़कों और पर्यटन के आंकड़ों से नहीं मापी जा सकती। असली विकास तब होगा जब पहाड़ का बच्चा अच्छी शिक्षा के लिए गांव छोड़ने को मजबूर न हो, मरीज को इलाज के लिए शहर की ओर न भागना पड़े और युवा रोजगार के लिए अपना घर न छोड़े। आजादी की 80वीं वर्षगांठ हमें यह याद दिलाती है कि देश केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या बड़े शहरों का नाम नहीं है। देश उन दूरस्थ गांवों का भी नाम है जहां एक बुजुर्ग आज भी उम्मीद लगाए बैठा है कि सरकार उसके दरवाजे तक पहुंचेगी। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें केवल यह नहीं पूछना चाहिए कि देश ने 79 वर्षों में क्या हासिल किया। हमें यह भी पूछना चाहिए कि अगले 20 वर्षों में हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। 2047 में जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे, तब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति हो सकता है। असली सवाल होगाकृक्या उस भारत में नागरिक अधिक स्वतंत्र, अधिक सुरक्षित, अधिक शिक्षित और अधिक सम्मानित होगा? आज तिरंगा हमें यही संदेश देता है कि सत्ता बदलती रहती है, सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन राष्ट्र और संविधान स्थायी होते हैं। इसलिए 80वें स्वतंत्रता दिवस पर सबसे बड़ा संकल्प यही होना चाहिए देश को केवल आर्थिक रूप से शक्तिशाली नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण, राजनीतिक रूप से जवाबदेह और लोकतांत्रिक रूप से मजबूत बनाना है। तिरंगा तभी सचमुच ऊंचा रहेगा, जब उसके नीचे खड़ा आखिरी नागरिक भी खुद को बराबर का भारतीय महसूस करेगा। यही आजादी का अर्थ है। यही स्वतंत्रता दिवस की असली कसौटी है।

गले में 'डिग्रिया' और आंखों में 'आक्रोश'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में चुनावी साल का कैलेंडर अभी पूरी तरह चुनावी नहीं हुआ है, लेकिन बेरोजगार युवाओं की बेचैनी ने सियासत का मौसम जरूर बदल दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं की मुलाकात को इसी बदलते माहौल की एक तस्वीर के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि कुछ बेरोजगार युवा राहुल गांधी से मिले। सवाल यह है कि वह अपनी बात लेकर राहुल गांधी तक क्यों पहुंचे? और उससे भी बड़ा सवाल क्या रोजगार, भर्ती, परीक्षा और युवाओं के भविष्य का मुद्दा कांग्रेस को उस वोटर के करीब ले जा रहा है, जिससे पिछले चुनावों में वह पर्याप्त दूरी पर दिखाई दी थी? देहरादून में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का केंद्र भी यही मुद्दे रहे थे। शिक्षा, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और पेपर लीक जैसे सवालों पर युवाओं ने अपनी बात रखी। कार्यक्रम में एक बेरोजगार युवक का डिग्रियों की माला पहनकर पहुंचना भी चर्चा का विषय बना था। यानी राहुल गांधी के सामने युवाओं की नाराजगी कोई अचानक पैदा हुई राजनीतिक कहानी नहीं है। कांग्रेस ने इसे सुनने और राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश पहले से शुरू कर रखी है।

यहां एक सावधानी जरूरी है। युवाओं की कांग्रेस से नजदीकी दिखाई देना और युवाओं का कांग्रेस के साथ आ जानाकृदो अलग बातें हैं। बेरोजगार युवा पहले नौकरी चाहता है, फिर राजनीति करता है। उसके लिए भाजपा या कांग्रेस से ज्यादा महत्वपूर्ण भर्ती की तारीख है। परीक्षा होगी या नहीं, परिणाम आएगा या नहीं, नियुक्ति मिलेगी या नहीं उसकी राजनीति इन सवालों के आसपास घूमती है। इसलिए राहुल गांधी से मुलाकात को सीधे कांग्रेस के पक्ष में वोट का संकेत मान लेना जल्दबाजी होगी। लेकिन भाजपा के लिए इसमें खतरे का

◆उत्तराखंड में युवा वोट की नई कहानी, बेरोजगारों की राहुल गांधी से मुलाकात
◆धांधली और पेपर लीक से टूटे सब्र के बांध ने युवाओं को दिल्ली तक दौड़ाया
◆2027 के चुनाव में बैकफुट पर खड़ी कांग्रेस को संजीवनी देंगे राज्य के युवा
◆आखिर क्यों स्थानीय नेताओं के बजाय राहुल से गुहार लगाने पहुंचे बेरोजगार

संकेत जरूर है। क्योंकि जब किसी सरकार के खिलाफ असंतोष बनता है तो विपक्ष को हमेशा अपना वोट बैंक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी-कभी सत्ता के खिलाफ जमा हो रहा सवाल ही विपक्ष के लिए राजनीतिक जगह बना देता है।

उत्तराखंड में भाजपा लगातार सत्ता में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार 2027 के चुनाव की तैयारी में है। कांग्रेस भी संगठन और चुनावी रणनीति को सक्रिय कर चुकी है। ऐसे में बेरोजगारी कांग्रेस के लिए केवल एक मुद्दा नहीं, बल्कि भाजपा को घेरने का संभावित राजनीतिक रास्ता बन सकती है। लेकिन भाजपा की परेशानी सिर्फ विपक्ष के सवालों से नहीं होगी। असली परेशानी तब होगी जब यही सवाल युवा मतदाता की निजी अनुभूति बन जाए, जिस युवा ने वर्षों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की है, जिसने फीस भरी है, फार्म भरा है, परीक्षा की तैयारी की है और फिर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते देखे हैंकृउसके लिए बेरोजगारी अखबार की खबर नहीं है। वह उसकी जिंदगी है। राजनीति में यही फर्क बहुत बड़ा होता है।

उत्तराखंड में रोजगार का सवाल पलायन से भी जुड़ा है। पहाड़ का युवा नौकरी के लिए देहरादून, हल्द्वानी, दिल्ली और दूसरे शहरों की ओर जाता है। गांव खाली होते हैं और चुनाव के समय यही गांव राजनीतिक भाषणों में विकास की कहानी बन जाते हैं। लेकिन युवा पूछ सकता हैकृअगर विकास हुआ है तो रोजगार मेरे गांव में क्यों नहीं है? यही सवाल कांग्रेस को राजनीतिक अवसर देता है और यही सवाल भाजपा के लिए चुनौती भी बन सकता है। राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय में छात्रों और युवाओं के सवालों को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश की है। उत्तराखंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम भी इसी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन राजनीति में संवाद और वोट के बीच लंबी दूरी होती है।

युवा राहुल गांधी को सुन सकता है,

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

'गंगाजल, गौमूत्र और सियासी जहर'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में अब राजनीति सिर्फ भाषणों और नारों तक सीमित नहीं रह गई है। मंच भी राजनीतिक संदेश देने लगे हैं और मंच के शुद्धिकरण की तस्वीरें राजनीति का नया हथियार बनती दिखाई दे रही हैं। किसी सार्वजनिक मंच पर कौन खड़ा हुआ, किसने क्या कहा और उसके बाद मंच को शुद्ध करने की जरूरत क्यों महसूस हुई इन सवालों ने सियासत को फिर गरमा दिया है। मुद्दा केवल इतना नहीं है कि मंच का शुद्धिकरण किसने कराया। असली सवाल यह है कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति की मौजूदगी को इतना अशुद्ध कैसे मान लिया गया कि उसके जाने के बाद मंच को पवित्र करने की जरूरत पड़ गई? राजनीति में मतभेद होते हैं। विचार अलग होते हैं। चुनाव में एक-दूसरे के खिलाफ प्रचार भी होता है। लेकिन जब राजनीतिक विरोध धीरे-धीरे सामाजिक और वैचारिक दूरी का प्रतीक बनने लगे, तब सवाल केवल राजनीति का नहीं रह जाता।

सार्वजनिक मंच किसी एक पार्टी की निजी संपत्ति नहीं होता। वह जनता का मंच होता है। वहां सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसान हो या छात्र, कर्मचारी हो या सामाजिक कार्यकर्ता हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। किसी के मंच पर आने से मंच अपवित्र और किसी दूसरे के आने से पवित्र हो जाता है तो फिर लोकतंत्र की पवित्रता का क्या होगा? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीति में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। मंच धोया जा सकता है, पानी से साफ किया जा सकता है, धार्मिक अनुष्ठान कराया जा सकता है, लेकिन समाज के भीतर पैदा की जा रही दूरी को किस पानी से धोया जाएगा?

राजनीतिक विरोध लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन विरोध को नफरत में बदल देना लोकतंत्र की कमजोरी है। उत्तराखंड की राजनीति में यह घटनाक्रम इसलिए भी गंभीर है क्योंकि राज्य की ~~सामाजिक संरचना रिश्तों और साझा जीवन~~

◆मंच के शुद्धिकरण पर सियासत तेज, सवाल मंच का नहीं, राजनीति की सोच का
◆भाषणों व नारों से आगे बढ़ी जंग, विरोधियों को अपवित्र ठहराने का नया पैंतरा
◆जनमंच भी किसी एक की बपौती बना, जनता की आवाज की पवित्रता का क्या
◆सत्ता और विपक्ष की इस गंदी लड़ाई में जनहित के असली मुद्दे चढ़ रहे हैं बलि

पर टिकी रही है। पहाड़ के गांव में राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन शादी-ब्याह, दुख-सुख और सामाजिक जीवन में लोग एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद भी गांव को उसी गांव में रहना होता है। फिर राजनीति ऐसी भाषा क्यों पैदा करे जिसमें सामने वाला राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि अशुद्ध दिखाई देने लगे? यही वह जगह है जहां सवाल भाजपा बनाम कांग्रेस से आगे निकल जाता है। सवाल किसी एक दल के चरित्र का नहीं, बल्कि हमारी राजनीतिक संस्कृति का है।

आज यदि किसी नेता के भाषण से असहमति है तो जवाब भाषण से दिया जाना चाहिए। किसी नीति से विरोध है तो उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। किसी बयान पर आपत्ति है तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होना चाहिए। लेकिन मंच को शुद्ध करके हम आखिर किसे संदेश दे रहे हैं? क्या जनता को यह बताया जा रहा है कि राजनीति में विरोधी के साथ बैठना भी अपवित्रता है? अगर ऐसा है तो फिर लोकतंत्र में संवाद कहां बचेगा? आज राजनीतिक दल संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनावी मंच पर नहीं, विरोधी के सम्मान में होती है, जिस दिन हम अपने विरोधी को बोलने का अधिकार देना बंद कर देंगे, उस दिन लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कमजोर हो जाएगा।

मंच का शुद्धिकरण शायद कुछ लोगों के लिए धार्मिक या राजनीतिक कर्मकांड हो सकता है। लेकिन जनता के लिए यह एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है क्या राजनीति अब विचारों की लड़ाई से निकलकर छुआछूत जैसी मानसिकता की तरफ बढ़ रही है? इस सवाल का जवाब राजनीतिक दलों को देना होगा। क्योंकि मंच चाहे जितनी बार धोया जाए, इतिहास तस्वीरों को नहीं धोता। तस्वीर में अगर कोई राजनीतिक विरोधी खड़ा था तो उसे मिटाया नहीं जा सकता और अगर उस तस्वीर के बाद मंच को शुद्ध करने की जरूरत पड़ी, तो आने वाली पीढ़ियां मंच से ज्यादा उस मानसिकता के बारे में सवाल करेंगी जिसने शुद्ध-अशुद्ध का यह पैमाना बनाया। लोकतंत्र में मंच की पवित्रता किसी व्यक्ति से तय नहीं होती। उसकी पवित्रता इस बात से तय होती है कि वहां हर नागरिक की आवाज के लिए जगह है या नहीं। मंच धोने से मंच साफ हो सकता है। लेकिन राजनीति में बढ़ती नफरत साफ नहीं होती। उसके लिए सोच बदलनी पड़ती है।

रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया

हरिद्वार(आरएनएस)। कांवड़ मेला संपन्न होने के बाद शहर में सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नगर निगम ने वृहद स्वच्छता अभियान चलाया। जिलाधिकारी और नगर आयुक्त के निर्देश पर 'हर घर तिरंगा, हर पग स्वच्छता अभियान' के तहत कांवड़ मार्गों, कांवड़ पटरी, पार्किंग क्षेत्रों और हाईवे की सर्विस रोडों पर विशेष सफाई कर कूड़े और अपशिष्ट का निस्तारण किया गया। बुधवार को शांतिकुंज के सहयोग से रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इसके अलावा कांवड़ मार्ग और कांवड़ पटरी, लालजीवाला, पंतदीप, चमगादड़ टापू और हाईवे किनारे स्थित सर्विस रोडों पर भी सफाई कराई गई। अभियान के दौरान कांवड़ मेले के दौरान जमा हुए कूड़े को हटाकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत निस्तारण किया गया।सफाई अभियान की निगरानी नगर निगम के मुख्य सफाई निरीक्षकों ने की। रोड़ी बेलवाला में मुख्य सफाई निरीक्षक संजय शर्मा, बैरागी कैंप में श्रीकांत, गुरुकुल कांगड़ी सर्विस रोड पर विकास छाछर, कांवड़ पटरी पर सुनील मलिक और लालजीवाला क्षेत्र में सफाई निरीक्षक धीरेंद्र सेमवाल के नेतृत्व में सफाई कार्य कराया गया। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने कहा कि कांवड़ मेले के दौरान नगर निगम की टीम ने व्यापक स्तर पर सफाई व्यवस्था संभाली। मेला समाप्त होने के बाद भी विशेष अभियान चलाकर कांवड़ मार्गों, पार्किंग क्षेत्रों, सर्विस रोड और अन्य प्रमुख स्थानों से अपशिष्ट हटाया गया है। अभियान के दौरान उपनगर आयुक्त दीपक गोस्वामी और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत समेत नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही।

महिलाओं को वीपीआरपी प्रशिक्षण दिया

चम्पावत(आरएनएस)। चम्पावत में महिलाओं को वीपीआरपी प्रशिक्षण दिया गया। इसका मकसद अंतिम छोर की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। चम्पावत विकास भवन में गुरुवार को वीपीआरपी प्रशिक्षण हुआ। मुख्य अतिथि सीडीओ डॉ. जीएस खाती ने बताया कि प्रशिक्षण में महिलाओं को एनआरएलएम के तहत ग्रामीण समृद्धि योजना की जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनर व जिला थिमेटिक एक्सपर्ट कैलाश चंद्र शर्मा और पाटी के ब्लॉक मिशन प्रबंधक रमेश सिंह पाटनी ने वीपीआरपी की रूपरेखा, आंकड़ों के संकलन, आजीविका संवर्द्धन और ग्राम पंचायत विकास योजना की जानकारी दी। कार्यक्रम में पीडी अजय सिंह, एपीडी विम्मी जोशी समेत सभी ब्लॉक मिशन मैनेजर एरिया कोऑर्डिनेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा कम्युनिटी कैडर आदि मौजूद रहे।

सफाई व जर्जर व्यवस्थाओं को लेकर एबीवीपी ने सौंपा ज्ञापन

हल्द्वानी(आरएनएस)। एमबीपीजी कॉलेज में साफ-सफाई और जर्जर व्यवस्थाओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कॉलेज इकाई ने प्राचार्य डॉ. एनएस बनकोटी को ज्ञापन सौंपा। परिषद ने महाविद्यालय के बीएससी और बीकॉम विभागों में नियमित सफाई व्यवस्था कराने की मांग उठाई।ज्ञापन में बीएससी की कक्षाओं में टूटी फॉल सीलिंग की मरम्मत, वॉशरूम की उचित सफाई, खराब ब्लैकबोर्ड को ठीक कराने या बदलने की मांग भी उठाई। कॉलेज इकाई अध्यक्ष आर्यन बेलवाल ने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराना महाविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि परिषद ने कॉलेज प्रशासन से एक सप्ताह के भीतर सभी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है।ज्ञापन सौंपने के दौरान धीरज बिष्ट, यतिन पांडेय, कमल पाटनी, मनोज फुलारा, तेजस खुल्बे आदि मौजूद रहे।

जसपुर में महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने को बन रहा वेसाइड अमेनिटीज

काशीपुर(आरएनएस)। सीडीओ दिवेश शाशनी ने नेशनल हाईवे पर ग्राम जगतपुर पट्टी में नवनिर्मित वे साइड अमेनिटीज का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने पूर्ण हो चुके कार्यों का जायजा लेने के साथ अभिलेखों का भी अवलोकन किया। सांसद निधि और जिला योजना से ग्राम जगतपुर पट्टी में बनाई जा रही वे साइड अमेनिटीज का उद्देश्य हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों को सुविधाएं और सुरक्षित सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ स्थानीय महिलाओं को आजीविका एवं स्वरोजगार से जोड़ना है। गुरुवार को निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने परिसर में उपलब्ध सुविधाओं, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया।उन्होंने अधिकारियों को शेष कार्य निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं को बेहतर बनाने और परिसर को साफ-सुथरा व व्यवस्थित रखने पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि वे साइड अमेनिटीज का प्रभावी संचालन स्थानीय महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस दौरान बीडीओ केके कांडपाल, जिला परियोजना प्रबंधक शुभांकर झा, अमित कुमार आदि रहे।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

पहाड़ के 'कल्यो' के स्वाद में बसा है अपनापन

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। पहाड़ का खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं रहा। इसमें मौसम है, मिट्टी है, मेहनत है और पीढ़ियों से चली आ रही जीवनशैली भी है। पहाड़ की रसोई में ऐसे कई व्यंजन हैं, जिनके नाम सुनते ही पुराने गांव, लकड़ी का चूल्हा और घर के आंगन की याद ताजा हो जाती है। इन्हीं में एक नाम है पैणु, जिसे कई इलाकों में कल्यो के नाम से भी जाना जाता है। पैणु पहाड़ी खानपान की उसी परंपरा का हिस्सा है, जिसमें उपलब्ध स्थानीय अनाज और दालों से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाता रहा है। पहाड़ में जब बाजार दूर थे और हर चीज आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी, तब घर की रसोई स्थानीय संसाधनों पर ही निर्भर रहती थी। यही मजबूरी धीरे-धीरे पहाड़ की विशिष्ट पाक संस्कृति बन गई।

पैणु या कल्यो की सबसे बड़ी खासियत इसका घरेलू स्वाद है। यह ऐसा भोजन है जिसमें बहुत अधिक मसालों या सजावट की जरूरत नहीं होती। स्थानीय सामग्री और पारंपरिक तरीके से पकाने पर इसका स्वाद अपने आप अलग पहचान बना लेता है। पहाड़ की बुजुर्ग महिलाएं आज भी ऐसे व्यंजनों को केवल पकाती नहीं हैं, बल्कि उनके साथ जुड़ी पूरी परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। किस मौसम में कौन सा अनाज उपयोग करना है, किस तरह भिगोना है और चूल्हे पर कितनी देर पकाना हैकृये बातें किसी किताब से नहीं, बल्कि अनुभव से सीखी जाती थीं।

पहाड़ के पारंपरिक भोजन की कहानी वहां की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी है। गांवों में खेती सीमित थी। जो पैदा होता था, उसी से सालभर का भोजन तैयार किया जाता था। मंडुवा, झंगोरा, गहत, भट्ट, मसूर, जौं और दूसरी स्थानीय उपज पहाड़ी भोजन

◆पेट भरने का जरिया नहीं, मौसम, मिट्टी और पीढ़ियों की जीवनशैली का संगम
◆जब बाजार दूर थे, तब स्थानीय अनाज और दालों से तैयार हुआ अनूठा जायका
◆पारंपरिक ज्ञान बुजुर्ग महिलाओं से अगली पीढ़ी तक पहुंच रही पहाड़ की परंपरा

का आधार रही हैं। इसलिए पैणु या कल्यो जैसे व्यंजन केवल स्वाद की चीज नहीं थे। वह स्थानीय आत्मनिर्भरता की पहचान भी थे। आज बाजार में पैकेटबंद खाद्य सामग्री की भरमार है। लेकिन जिस समय पहाड़ में बाजार तक पहुंचना कठिन था, उस समय घर की रसोई ही सबसे बड़ा बाजार थी। खेत से अनाज आया और सीधे चूल्हे तक पहुंचा।

पहाड़ की रसोई में भोजन अकेले नहीं बनता था। घर की महिलाएं मिलकर खाना तैयार करती थीं। एक तरफ चूल्हे पर दाल या सब्जी पकती, दूसरी तरफ अनाज साफ होता और आंगन में बच्चे खेलते रहते। पैणु या कल्यो जैसे व्यंजन इस सामूहिक जीवन का हिस्सा रहे हैं। इसलिए इनके स्वाद में केवल सामग्री नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट भी शामिल है। आज गैस चूल्हे और आधुनिक रसोई ने जीवन आसान कर दिया है। समय बचा है, मेहनत कम हुई है। लेकिन उसी के साथ सामूहिक रसोई की वह संस्कृति भी धीरे-धीरे कमजोर हुई है।

पलायन ने पहाड़ के खानपान को भी प्रभावित किया है। गांव खाली हुए तो कई पारंपरिक व्यंजन भी घरों की रसोई से गायब होने लगे। नई पीढ़ी को स्थानीय भोजन के बजाय बाजार के स्वाद की आदत अधिक होने लगी। ऐसे में पैणु या कल्यो जैसे व्यंजन केवल पुरानी याद नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत हैं। इन्हें बचाने का मतलब सिर्फ किसी एक पकवान को बचाना नहीं, बल्कि पहाड़ की खेती, बोली, परंपरा और जीवनशैली को बचाना है। आज जरूरत है कि पहाड़ी व्यंजनों को घरों तक सीमित न रखा जाए। स्थानीय मेलों, स्कूलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी भोजनालयों में इन्हें पहचान मिले। स्थानीय किसानों को पारंपरिक अनाज उगाने के लिए बेहतर बाजार मिले और युवा इन व्यंजनों को नए अंदाज में लोगों तक पहुंचाएं।

पैणु या कल्यो की कहानी हमें बताती है कि पहाड़ की असली पहचान केवल उसकी ऊंची चोटियों और खूबसूरत वादियों में नहीं है। उसकी पहचान उसकी रसोई में भी छिपी है। जिस भोजन को कभी पहाड़ की मजबूरी समझा जाता था, आज वही भोजन बदलते दौर में उसकी खास पहचान बन सकता है। क्योंकि पहाड़ का स्वाद जितना पुराना है, उतना ही भविष्य के लिए जरूरी भी। पैणु हो या कल्यो यह सिर्फ एक व्यंजन का नाम नहीं, पहाड़ की उस रसोई की कहानी है जहां सादगी में स्वाद और कम साधनों में आत्मनिर्भरता पैदा होती थी।

बदरगांव में मंत्री विनोद सुयाल को ग्रामीणों ने घेरा

पौड़ी (आरएनएस)। सरकार के जन संवाद कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत गोर्थीकांडा के बदरगांव पहुंचे युवा कल्याण राज्य मंत्री विनोद सुयाल को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। उनके यहां पहुंचते ही ग्रामीणों ने उनका घेराव कर दिया। ग्रामीणों ने मुनेठ-बदरगांव मार्ग की बदहाली पर उनको खरी खोटी सुनाई। साथ ही काश्तकारों को अब तक मुआवजा न मिलने का मुद्दा भी उठाया।ग्रामीणों ने बताया कि सात वर्ष पहले एक करोड़ की लागत से बनी मुनेठ-बदरगांव पांच किमी सड़क का लाभ आज तक नहीं मिल पाया है। लोनिवि की ओर से डंपिंग जोन न बनाने से मलबे के कारण वाहनों का गुजरना मुश्किल हो गया है और जीरो प्वाइंट से भैस्वाड़ी बैंड तक डेंजर जोन बनने से लोग तीन से चार किमी पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। बीमारों और गर्भवती महिलाओं को दो हजार रुपये देकर डंडी-कंडी से अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। सिंचाई गूल टूटने से खेत बंजर हो गए हैं और काश्तकारों को अब तक भूमि का मुआवजा भी नहीं मिला है।ग्रामीणों की नाराजगी जताई कि दो बार भाजपा प्रत्याशी विनोद कंडारी को चुनने के बाद भी आज प्रदेश के राज्य मंत्री को तीन किमी पैदल चलकर बदरगांव पहुंचना पड़ रहा है जबकि लोनिवि के मलबे से जालीकांडा गांव के बारह परिवारों पर भी खतरा मंडरा रहा है। राज्य मंत्री विनोद सुयाल ने ग्रामीणों से ज्ञापन लेकर समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री से भेंट कराने का भरोसा दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें आगे जाने दिया।

एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर, राजनीतिक दलों के साथ डीएम ने की समीक्षा बैठक

अल्मोड़ा(आरएनएस)। जनपद में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को पारदर्शी, त्रुटिरहित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बुधवार को जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और उनके द्वारा नामित बीएलए-1 के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुनरीक्षण प्रक्रिया, नोटिसों के निस्तारण और सुनवाई व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने कहा कि एसआईआर के तहत प्राप्त नोटिसों की सुनवाई पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार सत्यापन करते हुए समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 98,529 नोटिसों की सुनवाई के लिए 856 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं। बैठक में विधानसभावार सुनवाई कार्यक्रम की भी जानकारी दी गई। द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र में 16,962 नोटिसों की सुनवाई 149 मतदेय स्थलों पर 18 अगस्त तक चल रही है। सल्ट विधानसभा क्षेत्र में 18,668 नोटिसों की सुनवाई 112 मतदेय स्थलों पर 3 सितंबर तक होगी। रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में 12,०2० नोटिसों की सुनवाई 14० मतदेय स्थलों पर 2 सितंबर तक निर्धारित है। इसी क्रम में सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में 14,०56 नोटिसों की सुनवाई 156 मतदेय स्थलों पर 26 अगस्त तक, अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र में 19,266 नोटिसों की सुनवाई 142 मतदेय स्थलों पर 31 अगस्त तक तथा जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में 17,557 नोटिसों की सुनवाई 187 मतदेय स्थलों पर 26 अगस्त तक संपन्न कराई जाएगी। बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सामने आ रही समस्याओं और प्रक्रियात्मक विषयों पर अपने सुझाव रखे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सुझावों और शिकायतों का नियमानुसार एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी भरत सिंह रावत, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखण्ड शासन
जय हिन्द!
80 वें
स्वतन्त्रता दिवस
15 अगस्त
की
हार्दिक शुभकामनाएँ
समस्त देशवासियों को स्वतन्त्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं स्वतन्त्रता संग्राम के नायकों व देश की सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों को नमन करता हूँ। आईये, इस स्वतन्त्रता दिवस पर हम सभी मिलकर उत्तराखण्ड राज्य तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध हों।
पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड
हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए सिरे से परिभाषित करता है। स्वतन्त्रता दिवस के इस अवसर पर हमें नये संकल्पों को आधार बनाना है, नए संकल्पों को लेकर चल पड़ना है। आइए, एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लें, जो विकसित भी हो, आत्मनिर्भर भी हो और अपनी विरासत पर गर्व भी करे।
नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री
सेवा - सुशासन - समर्पण
• राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून हुआ लागू, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता कायम होने से अब युवाओं का चयन एक से अधिक विभागों में हो रहा है।
• बीते 5 वर्षों में 34000 से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी।
• राज्य के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य
• राज्य में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का हुआ आयोजन। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर बनाया नया रिकॉर्ड।
• हल्द्वानी में राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की हो रही स्थापना।
• स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गौलापार एवं महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के
• राज्य के खिलाड़ियों का दैनिक भोजन भत्ता 250 रुपए से बढ़ाकर भारतीय खेल प्राधिकरण की भांति 480 रुपए प्रतिदिन, प्रति खिलाड़ी किया गया।
• उत्तराखण्ड फिल्म नीति के तहत FTII से पासआउट युवाओं को मिली छात्रवृत्ति। पाठ्यक्रम पर हुए व्यय के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी को 75 प्रतिशत एवं सामान्य

- राज्य के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित, जिसमें वर्तमान में 5 कॉलेज संचालित हैं एवं 2 अन्य कॉलेजों का निर्माण कार्य जारी है।
- राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की कुल संख्या वर्ष 2024-25 में बढ़कर 79394 हो गई है। जो वर्ष 2021-22 में 59798 थी।
- एमएसएमई के अंतर्गत रोजगार पाने वालों की संख्या वर्ष 2025 में बढ़कर 456605 हो गई है। जो 2022 में 343922 थी।
- राज्य में स्टार्टअप की संख्या 2024-25 में बढ़कर 1750 हो गई है। जो 2017 तक शून्य थी, और वर्ष 2021-22 में 702 थी।
- राज्य सरकार द्वारा शुरु की गई मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना। इस योजना का बजट बढ़ाकर ₹ 75 लाख से ₹ 3.3 करोड़ किया गया। 147 बच्चों को अब तक विदेशी भाषा का दिया गया प्रशिक्षण एवं 92 बच्चों को विभिन्न देशों में रोजगार मिला है।
- पी.एम.श्री योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य के 141 विद्यालयों, द्वितीय चरण में 84 विद्यालयों को चयनित किया गया।
- देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 लागू करने वाला राज्य बना उत्तराखण्ड।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की हुई शुरुआत।
- राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु लैब ऑन व्हील कार्यक्रम का हो रहा संचालन। सभी जिलों में खोले जा रहे विज्ञान केंद्र।
- प्रतियोगी परीक्षाओं तथा विभिन्न प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु तथा योग्यता निर्धारण के लिए होने वाली परीक्षाओं (केट, मेट, गेट आदि) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए निःशुल्क ऑन लाईन कोचिंग हेतु मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के संचालन को मिली मंजूरी।
- स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गौलापार एवं महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के संचालन के लिए विभिन्न पद कैबिनेट ने किए स्वीकृत।
- नई खेल नीति के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का ऐतिहासिक फैसला।
- मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना तथा खेल किट योजना जैसी विभिन्न योजनाएं हो रही संचालित।

विकास भी, विरासत भी

एसटी, एससी, ओबीसी की 75 प्रतिशत एवं सामान्य अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही।

- मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के प्रदेश में करीब 3900 उभरते खिलाड़ियों को दी जा रही 1500 रुपये प्रतिमाह की खेल छात्रवृत्ति।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं (जैसे ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल आदि) में पदक जीतने वाले या भाग लेने वाले खिलाड़ियों को राजकीय सेवाओं में 4 प्रतिशत खेल कोटे का मिलेगा लाभ।
- भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064 किया लांच। 1905 सी.एम. हेल्पलाइन नंबर से जनता को मिल रही सहूलियत।
- नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक-2026 में उत्तराखण्ड को पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त।
- स्वतंत्र भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश में प्रथम राज्य बना उत्तराखण्ड।
- राज्य में सशक्त भू-कानून, सख्त धर्मान्तरण विरोधी कानून एवं दंगारोधी कानून हुआ लागू।
- राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत एवं राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण हुआ लागू।
- राज्य में उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का हुआ गठन, इसके अंतर्गत मदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद प्राधिकरण तय करेगा पाठ्यक्रम। यह प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करेगा।
- शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर किया 50 लाख रुपए।
- परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर की गई 2 करोड़।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी

www.uttarainformation.gov.in | DIPR_UK | UttarakhandDIPR | UttarakhandDIPR

दून वैली मेल देहरादून, 15 अगस्त 2026
www.dunvalleymail.com

अदवाणी के जंगल में पेड़ काटने पर भड़के ग्रामीण

नई टिहरी(आरएनएस)। अदवाणी के आरक्षित वन क्षेत्र में फायर लाइन बनाने के लिए चीड़ के हरे पेड़ों के कटान का ग्रामीणों ने विरोध किया। बृहस्पतिवार को हुई खुली बैठक में ग्रामीणों ने पेड़ों के कटान पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि कटान नहीं रुका तो क्षेत्र में दूसरी बार चिपको आंदोलन शुरू किया जाएगा।ग्राम प्रधान विजय सिंह भंडारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीणों ने फायर लाइन की आड़ में हरे चीड़ के पेड़ काटे जाने पर रोष जताया। ग्रामीणों के विरोध के बाद पेड़ काटने आए श्रमिक मौके से लौट गए। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी किशोर नौटियाल ने ग्रामीणों से वार्ता की। उन्होंने बताया कि फायर लाइन बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे हरे पेड़ों का कटान नहीं होने देंगे। वन विभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी नौटियाल और रेंजर शैलेंद्र सिंह नेगी ने फिलहाल पेड़ नहीं काटने का आश्वासन दिया।पर्यावरणविद विजय जड़धारी ने कहा कि फायर लाइन के नाम पर बड़े हरे चीड़ के पेड़ों को काटने की अनुमति देना उचित नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 1978 में इसी अदवाणी के जंगल में चिपको आंदोलन हुआ था। तब भी जंगल को बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। ग्रामीणों ने बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि यदि जंगल में पेड़ों का कटान किया गया तो क्षेत्र में दूसरी बार चिपको आंदोलन चलाया जाएगा।अदवाणी क्षेत्र में 15 मीटर चौड़ी फायर लाइन बनाने के लिए 15० से अधिक हरे चीड़ के पेड़ों के कटान की अनुमति है। इनमें से कुछ पेड़ वन विभाग द्वारा पहले ही काटे जा चुके हैं। बैठक में जन जागृति संस्थान के अध्यक्ष अरण्य रंजन, दयाल भाई, नरेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, रविंद्र रावत, विजयपाल सिंह, किशन सिंह रावत, रणजीत सिंह, कुलबीर सिंह रावत, पूर्व प्रधान प्रमिला देवी, सुविधा देवी आदि मौजूद रहे।

देवग्राम के 27 परिवारों के विस्थापन का प्रस्ताव शासन को भेजने की संस्तुति

चमोली(आरएनएस)। जिला स्तरीय पुनर्वास समिति ने देवग्राम के 27 परिवारों के विस्थापन संबंधी प्रस्ताव को संस्तुति के लिए शासन को भेजने पर सहमति व्यक्त की। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विस्थापन संबंधी प्रस्ताव की सभी अभिलेख व औपचारिकताएं पूरी करते हुए शीघ्र प्रस्ताव शासन को भेजा जाए।बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई। इसमें तहसील ज्योतिर्मठ के अंतर्गत देवग्राम के 27 परिवारों के विस्थापन संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा हुई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने बताया कि इन 27 परिवारों के विस्थापन के लिए एक करोड़ 21 लाख 25 हजार रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए भवन निर्माण, गोशाला, विस्थापन भत्ता, विस्थापित परिवारों को पुनर्वास स्थल पर व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता सहित अन्य मदों को शामिल किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि देवग्राम का दो बार भू-वैज्ञानिक सर्वे कर चुके हैं।

सू- दोकू क्र.036

	9		1	6		2		7
3								
		6					9	
7			5		1		3	
	8			9		6		2
		4					7	
	3				2	9		6
6		7	3					4
	4			1		7	8	

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.35का हल

2	6	3	9	8	7	1	5	4
8	5	1	3	2	4	6	7	9
9	4	7	1	5	6	8	2	3
3	9	8	6	7	1	5	4	2
6	1	2	5	4	3	9	8	7
5	7	4	8	9	2	3	1	6
1	2	6	7	3	5	4	9	8
4	8	5	2	6	9	7	3	1
7	3	9	4	1	8	2	6	5

देशज समाज ने हक और सुविधाओं की मांगें उठाईं

रुद्रपुर(आरएनएस)। देशज सर्वोदय सांस्कृतिक समिति ने देशज समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर गुरुवार को एडीएम पंकज उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। समिति ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में देशज समाज ने भी पर्वतीय समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया, लेकिन वर्तमान में समाज स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहा है। ज्ञापन के माध्यम से शासन-प्रशासन स्तर पर समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में प्रदेश के विभिन्न जिलों में लंबे समय से निवास कर रहे देशज समाज के लोगों को नजूल भूमि का स्वामित्व देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।साथ ही स्थायी निवास, ओबीसी प्रमाणपत्र, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनवाने में आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश देने की मांग की गई। समिति ने आरटीई के तहत देशज समाज के बच्चों को निजी विद्यालयों में शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराने की भी मांग रखी। समिति ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान हटाए गए देशज समाज के मतदाताओं के नाम दोबारा सूची में शामिल कराने, लंबे समय से उत्तराखंड में स्थायी रूप से निवास कर रहे लोगों को 25० वर्गमीटर से अधिक भूमि खरीदने का अधिकार देने और देशज समाज के लिए अन्य सामाजिक संगठनों की तर्ज पर भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग भी की। इसके अलावा सरकारी योजनाओं, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और बैंक वित्तपोषित रोजगार योजनाओं में देशज समाज की आबादी के अनुपात में पात्र लोगों को लाभ देने की मांग की गई। विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय निकायों में समाज की जनसंख्या के अनुपात में उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई। ज्ञापन में थारू-बुक्सा समाज को तराई क्षेत्र में आवंटित भूमि पर हुए कथित अवैध कब्जों को हटाने और आवंटित भूमि की चकबंदी शीघ्र कराने की मांग भी की। इस दौरान अधिवक्ता कल्याण सिंह, जुयक वल्लभ रेवाड़, अध्यक्ष देशज समाज, श्रीश्री 1००8 बाबा शिवानंद जी महाराज उर्फ दूधिया बाबा, डॉ.केपी सिंह, सबाहत हुसैन खान, बुद्ध सेन गंगवार, जेएन तिवारी, वीरू सिंह, विजय राठौड़, डॉ. उमा शंकर, पुनीत तिवारी, अनूप सिंह, गीता शर्मा, अभय प्रताप सिंह, मैदालाल चंद्रा, राम प्रसोधे चंद्रा, लाखन सिंह, हेमंत चौहान, डॉ. भूपेंद्र गंगवार, विनोद विजय पाल, ओमकार और सत्यपाल आदि मौजूद रहे।

वादाखिलाफी कर रही है कार्यदायी संस्था

चम्पावत(आरएनएस)। थ्वालखेड़ा के ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था पर वायदाखिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शारदा कॉरिडोर के तहत बन रही सुरक्षा दीवार में उनकी जरूरतों को ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन भेजा है। थ्वालखेड़ा के ग्रामीणों ने डीएम मनीष कुमार को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन मे कहा है कि टनकपुर शारदा रिवर फ्रंट कॉरिडोर परियोजना के तहत सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है। लेकिन दीवार निर्माण में उनकी सुविधा और आवागमन का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कहा कि ग्रामीणों के निकास और आवागमन मार्ग को बंद किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि मार्ग संकरा होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि इससे पूर्व कार्यदायी संस्था ने ग्रामीणों के हितों का ध्यान रखने की बात कही थी। जिसके लिए संयुक्त निरीक्षण भी किया गया था। ज्ञापन भेजने वालों में प्रधान हेमा जोशी, सतीश पांडेय, नारायण रावत, मनोज जोशी, नीरज जोशी, राहुल, पीयूष अवस्थी, प्रदीप नेगी, हेमा पांडेय, ममता, रेखा, भावना, कमला देवी, चंचला देवी और देवकी देवी शामिल रहीं।

वन संपदा बनीं हाईवे चौड़ीकरण में रोड़ा, तीन किमी पर काम रुका

पौड़ी(आरएनएस)। राष्ट्रीय राजमार्ग पौड़ी-कोटद्वार के चौड़ीकरण पर पौड़ी के बाहरी हिस्से में वन संपदा रोड़ा बन सकती है। गहड़ गांव की छतरी से बुआखाल के समीप गल्ला गोदाम तक करीब तीन किमी हिस्से में चौड़ीकरण का काम रुकने की आशंका है। सघन मिश्रित वन क्षेत्र होने के कारण वन विभाग ने इस हिस्से में चौड़ीकरण का कार्य फिलहाल रोक दिया है। साथ ही रिपोर्ट उच्चाधिकारियों और शासन को भेजी है।वन विभाग के अनुसार गहड़ गांव से गल्ला गोदाम तक के करीब तीन किमी के हिस्से में बांज, बुरांश, देवदार, काफल समेत अन्य प्रजातियों के 22०० से अधिक पेड़-पौधे हैं। विभाग का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए कटिंग होने पर बड़ी संख्या में मिश्रित वन संपदा नष्ट होगी। वर्तमान में कोटद्वार से पौड़ी और श्रीनगर तक हाईवे के चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में तीन किमी हिस्से में शासन से निर्णय आने तक काम प्रभावित रह सकता है। इससे हाईवे चौड़ीकरण की परियोजना की गति पर भी असर पड़ना तय है।

डोबरा पार्किंग को हेरिटेज के रुप में विकसित करें

नई टिहरी(आरएनएस)। डीएम नितिका खंडेलवाल ने जाख-डोबरा मोटर मार्ग और डोबरा- चांठी में निर्माणधीन पार्किंग के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मार्ग पर प्रस्तावित व्यू प्वाइंट, सेल्फी प्वाइंट और उनके समीप प्रस्तावित छोटी पार्किंग के लिए चयनित स्थलों का निरीक्षण करते हुए कहा कि जिन स्थानों पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, वहां शीघ्र कार्य शुरू करें।सडक चौड़ीकरण का कार्य निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जहां ग्रामीणों की आपत्तियां और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही है, वहां संबंधित ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए कार्य शुरू करें। ?डोबरा चांठी में पार्किंग का निरीक्षण करने के दौरान डीएम ने प्रस्तावित कार्यों और वहां उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली।पार्किंग में 49 चार पहिया वाहनों, 4 ईवी चार पहिया, 12० दुपहिया वाहन और 8 बसें पार्क की जा सकेंगी।

सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप, कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

रुद्रपुर(आरएनएस)। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के निर्देश पर भाजपा सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को डीडी चौक पर प्रदर्शन किया।कांग्रेसियों ने नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कथित रूप से अराजक तत्व कहने का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार और नैनीताल एसएसपी का पुतला दहन किया।

महानगर कांग्रेस अध्यक्ष ममता रानी और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आठ अगस्त को हल्द्वानी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली में शामिल होने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नैनीताल पुलिस-प्रशासन ने जगह-जगह रोककर परेशान किया।

उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। ममता रानी और राजकुमार ठुकराल ने कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से घबरा गई है और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर कांग्रेस के कार्यक्रमों एवं रैलियों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है।उन्होंने कहा कि जनता भाजपा की कथित नीतियों और हथकंडों को समझ चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी।उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक एवं जनहित के मुद्दों को लेकर अपना संघर्ष जारी रखेगी। प्रदर्शन में उमा सरकार, ज्योति टम्टा, मधु सिकदर, कमल चुघ, संध्या गुप्ता, प्रदीप यादव, विकास बंसल, रंजीत गुप्ता, जमुना प्रसाद, राजू गुप्ता, मोहन भारद्वाज, मुख्तार हुसैन, मसूद, दानिश खान, दीपक प्रकाश, जगदीश, सतनाम सिंह, सुनील चुघ, प्रीति साना, उमर अली, योगेश चौहान, मोनिका ढाली, आसित वाला, दर्शन कोली, भूपेंद्र सिंह, सेवाराम, बाबू विश्वकर्मा, आबिद हुसैन, रणजीत तिवारी, देवानंद, बलाई विश्वास, सरोज शर्मा, इंद्रजीत सिंह, अशफाक, हरभजन सिंह, ललित बिष्ट, सपन ओझा, रामपत मंडल, अशोक राय, रामकुमार गुप्ता, राजेंद्र शर्मा, खेम सिंह, कैलाश रावत, केरू मंडल, जावेद, रेहान, नासिर, अकबर अली आदि मौजूद रहे।

इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का भूकंप, 22 लोगों की मौत!

संवाददाता

नइ दिल्ली। इंडोनेशिया के तट पर शनिवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कई इमारतें हिलती हुई नजर आईं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.7 आंकी गई। इस तेजी का भूकंप काफी शक्तिशाली माना जाता है और इससे इमारतों को भारी नुकसान हुआ। इस भूकंप के कारण 22 लोगों की मौत हो चुकी है।

भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई और कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने आशंका जताई कि भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। भूकंप शनिवार को स्थानीय समयानुसार सुबह पांच बजकर 58 मिनट पर इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र में 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। रिपोर्टों के अनुसार, 20 लोगों की मौत हो चुकी है, छह लोग घायल हैं और दो लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। हमारा ध्यान मलबे के नीचे दबे पीड़ितों को खोजने पर केंद्रित होगा।ष शुक्रवार को भारत में भी कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि, इनकी तीव्रता बेहद कम थी।

तमिलनाडु में नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठियां दी जाएंगी!

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शनिवार को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फोर्ट सेंट जॉर्ज से अपना पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। इस कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने राज्य सचिवालय में तिरंगा फहराया और अपनी सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं के बारे में बताया, जो सामाजिक कल्याण, पारदर्शिता और सुशासन पर केंद्रित हैं। उनके भाषण की मुख्य बात राज्य भर में नवजात बच्चों के लिए एक कल्याणकारी योजना की घोषणा थी। अगले महीने शुरू होने वाली इस पहल के तहत, लगभग 755.83 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठियां दी जाएंगी।

उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार को खत्म करना आजादी के बराबर है, सरकार इसी लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। हम अपनी सरकार के खिलाफ काम करने वाली ताकतों और साजिशों को हराएंगे। 15 सितंबर को, 755.83 करोड़ रुपये की लागत से नवजात शिशुओं के लिए सोने की अंगूठी उपहार योजना शुरू की जाएगी।

बारिश में 'धंस' रहा उत्तराखंड...

◀◀ पृष्ठ 1 का शेष

भूगर्भीय अध्ययन हो। पानी की निकासी को प्राथमिकता दी जाए और पुराने भूस्खलन क्षेत्रों की नियमित निगरानी हो। बारिश थम जाएगी। धूप निकलेगी। सड़कें फिर सामान्य हो जाएंगी। बाजारों में रौनक लौट आएगी। लेकिन जो पहाड़ बारिश के दौरान कमजोर हुआ है, वह खतरा खत्म होने के बाद भी कमजोर रह सकता है। इसलिए अभी किए गए अस्थायी मरम्मत कार्यों के साथ-साथ दीर्घकालिक सुरक्षा योजना जरूरी है। क्योंकि उत्तराखंड में सवाल सिर्फ सड़क बचाने का नहीं है। सवाल सड़क के किनारे बसे बाजारों, दुकानों और घरों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा का भी है।

बारिश हर साल आएगी। पहाड़ भी अपनी जगह रहेगा। अब फैसला यह करना है कि विकास की हमारी रफ्तार पहाड़ की सहनशीलता के साथ चलेगी या हर मानसून हमें फिर उसी सवाल के सामने खड़ा करेगी कि सड़क बची या पहाड़? और अगर पहाड़ ही खिसक गया तो सड़क किसके लिए?

गले में 'डिग्रिया' और आंखों में ..

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

बेरोजगारी पर कांग्रेस से सहमत हो सकता है, सरकार से नाराज भी हो सकता है लेकिन मतदान के समय वह दूसरे मुद्दों पर फैसला कर सकता है। उत्तराखंड में राष्ट्रवाद, सैनिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पर्यटन, स्थानीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और क्षेत्रीय समीकरण भी चुनावी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए कांग्रेस के लिए सबसे कठिन काम होगा युवाओं की नाराजगी को स्थायी राजनीतिक भरोसे में बदलना। राहुल गांधी से बेरोजगारों की मुलाकात को भाजपा के लिए खतरे की घंटी कहा जा सकता है, लेकिन चुनाव का परिणाम नहीं। खतरा तब बनेगा जब बेरोजगारी का सवाल जाति, क्षेत्र और स्थानीय समीकरणों से ऊपर उठकर व्यापक युवा मुद्दा बन जाए। खतरा तब बनेगा जब युवा यह तय कर ले कि उसकी सबसे बड़ी समस्या सरकार की नीति है और उसका राजनीतिक विकल्प कांग्रेस है। अभी ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तराखंड का युवा अब सिर्फ भाषण सुनने वाला युवा नहीं है। वह सवाल पूछ रहा है और लोकतंत्र में सत्ता के लिए सबसे कठिन समय वही होता है, जब सवाल पूछने वाला मतदाता सवाल के साथ मतदान केंद्र तक पहुंचता है।

कांग्रेस के लिए यह अवसर है। भाजपा के लिए चेतावनी और बेरोजगार युवाओं के लिए शायद यह सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि अपनी आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने की कोशिश है। आखिर चुनाव में नेता बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन फैसला उस युवा को करना है, जिसने डिग्री हाथ में लेकर वर्षों इंतजार किया है नौकरी का, न्याय का और अपने भविष्य का।

मुख्यमंत्री ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में किया ध्वजारोहण

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण से पहले मुख्यमंत्री एवं उपस्थित अधिकारियों-कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से 'वंदे मातरम्' का गायन किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा मां भारती की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन करते हुए उनका स्मरण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर बलिदानियों ने जिस सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था, उसे साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ योगदान देना होगा। सामूहिक प्रयासों और जनभागीदारी से ही देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के समग्र, संतुलित और सतत विकास के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में सभी के सहयोग और सहभागिता से उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण कराता है।

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसएसपी द्वारा पुलिस लाइन में किया ध्वजारोहण

संवाददाता

देहरादून। 80 वें स्वतंत्रता दिवस पर एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण कर सभी अधिनस्थों को कर्त्तव्यनिष्ठा एवं देश सेवा की शपथ दिलायी।

आज यहां 80 वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में शहीदों को नमन करते हुए ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा उपस्थित सभी अधिनस्थों को कर्तव्यनिष्ठा एवं देश सेवा की शपथ दिलाई गई। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर शहीदों को याद कर उनसे प्रेरणा लेने तथा पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ देश सेवा व अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उपस्थित पुलिस कर्मियों को प्रेरित किया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशिष्ट कार्य के लिए पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क षसिल्वरष से सम्मानित अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशस्ति डिस्क प्रदान कर सम्मानित किया गया साथ ही सराहनीय कार्यो के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक तथा पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड प्रशस्ति डिस्क प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम को पढ़कर उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों को अवगत कराया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद देहरादून के सभी थाना/चौंकियो/कार्यालयों में उपस्थित अधिकारियों द्वारा झंडारोहण कर पुलिस कर्मियों को देश सेवा की शपथ दिलाई गई। दून पुलिस परिवार की ओर से सभी प्रदेश एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क सिल्वर (विशिष्ट कार्य हेतु) से अधिकारी/कर्मचारी जितेंद्र चौधरी, पुलिस अधीक्षक अपराध/यातायात, प्रमोद कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमती जया बलूनी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रथम, स्वप्निल मुयाल, क्षेत्राधिकारी नगर, श्रीमती नीलम बमराडा, मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस से सम्मानित किया।

पुलिस महानिदेशक ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलायी

संवाददाता

देहरादून। स्वतंत्रता दिवस-2026 के अवसर पर पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में दीपम सेठ, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ने ध्वजारोहण कर सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इसके उपरान्त पुलिस महानिदेशक महोदय ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर चयनित पुलिस कर्मियों को पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क 'गोल्ड' एवं पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क 'सिल्वर' एवं "पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सभी को बधाई दी। अपने सम्बोधन में पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ने कहा साथियों, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आज का यह दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, वीर आजादी के नायकों और अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करने का अवसर देता है, जिनके त्याग, साहस और बलिदान के कारण आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं। साथियों, राष्ट्र की एकता और अखंडता, संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। इस दायित्व के निर्वहन में हमारे पुलिसकर्मी सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे हैं।

आज पदक एवं सम्मान-चिह्न प्राप्त करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मैं पूरे पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे गर्व है कि उत्तराखण्ड पुलिस ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पेशेवर दक्षता और कार्यकुशलता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री के रोड शो में सुरक्षा प्रबन्धन की कड़ी चुनौती से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में आयोजित पांच दिवसीय न्याय संहिता प्रदर्शनी के सफल आयोजन तक, पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन किया है।

विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा और कांवड़ मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को बेहतर समन्वय के साथ संभालते हुए हमने सुरक्षा, सेवा और आस्था तीनों के बीच संतुलन बनाए रखा। उत्तराखण्ड पुलिस की हर सफलता के पीछे आपके परिश्रम, अनुशासन और समर्पण की कहानी है। मैं आप सभी के जज्बे की सराहना करता हूँ।

स्वतंत्रता हमें विरासत में मिली है, लेकिन राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी की है: सीएस

संवाददाता

देहरादून। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सचिवालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड आनन्द बर्द्धन ने प्रदेशवासियों, सचिवालय परिवार, उत्तराखण्ड पुलिस एवं पीएसी के जवानों, राजकीय इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान को स्मरण करने का दिन है, जिनके संघर्ष से आज भारत एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और संप्रभु राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्रता हमें विरासत में मिली है, लेकिन राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी की है।

उन्होंने कहा कि आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सामरिक क्षेत्रों में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं, युवा

विश्वभर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं और डिजिटल तकनीक ने शासन एवं नागरिक सेवाओं के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन किया है। अब हमारा लक्ष्य ऐसा समावेशी, सतत और गुणवत्तापूर्ण विकास सुनिश्चित करना है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिले और विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड की 25 वर्षों की यात्रा आत्मावलोकन और भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। राज्य का गठन केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं था, बल्कि इसके पीछे पर्वतीय क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों और विकास की आकांक्षाओं का लंबा संघर्ष रहा है। उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, पर्यटन, डिजिटल कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसके बावजूद पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन, रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन, दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं शिक्षा की पहुंच, आपदा जोखिम को कम करना, जल स्रोतों का संरक्षण और हिमालयी पारिस्थितिकी की रक्षा जैसी चुनौतियों पर निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सफलता में उत्तराखण्ड की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा लक्ष्य 'विकसित भारत के साथ विकसित उत्तराखण्ड' होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का अर्थ केवल बड़े शहरों और बड़ी परियोजनाओं से नहीं है। विकसित उत्तराखण्ड वह होगा, जहां पहाड़ का युवा अपने गांव में रहकर सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर सके, महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों, प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रत्येक नागरिक को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। गांव सड़क, इंटरनेट और आधुनिक सुविधाओं से जुड़े हों तथा विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के पूरक बनें।

टीएचडीसी टनल में रेस्क्यू अभियान जारी

◆एक और श्रमिक बाहर निकाला गया, दो की तलाश जारी

हमारे संवाददाता

चमोली। मायापुर (पीपलकोटी) स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में 13 अगस्त को हुई दुर्घटना के बाद लापता श्रमिकों की तलाश एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। रेस्क्यू अभियान के दौरान एक और श्रमिक को टनल से बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर भेजा गया है।

टनल में लापता दो अन्य श्रमिकों की तलाश युद्धस्तर पर जारी है। रेस्क्यू टीमें टनल के भीतर लगातार सर्च अभियान चला रही हैं। अभियान के दौरान टनल में मौजूद पानी की निकासी का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इसके लिए सक्शन पंपों सहित अन्य आवश्यक उपकरणों की मदद ली जा रही है, ताकि टनल के भीतर रेस्क्यू टीमों की आवाजाही सुगम हो सके और संभावित स्थानों तक पहुंचकर लापता श्रमिकों की खोज की जा सके। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तथा संबंधित विभागों की टीमें आपसी समन्वय के साथ राहत एवं बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। रेस्क्यू कार्य की लगातार निगरानी की जा रही है तथा अभियान को गति देने के लिए आवश्यक संसाधन एवं उपकरण मौके पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

प्रशासन द्वारा लापता दोनों श्रमिकों की तलाश को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी संभावित स्थानों पर सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीमों द्वारा पूरी तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है और श्रमिकों तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

बंशीधर तिवारी ने विभागीय परिसर में किया ध्वजारोहण

संवाददाता

देहरादून। सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग के महानिदेशक बंशी धर तिवारी ने विभागीय परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं।

आज यहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग के महानिदेशक बंशी धर तिवारी ने विभागीय परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। महानिदेशक तिवारी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान का स्मरण कराता है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर अपर निदेशक आशीष त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान, उपनिदेशक मनोज श्रीवास्तव, रवि बिजारनीया, श्रीमती अर्चना सहित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

'बाबा भी मिला रहे हैं कॉकरोच के सुर में सुर'

संवाददाता

हरिद्वार। योगगुरु बाबा रामदेव ने जेन-जी आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में चारों तरफ हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं। वहां टीचर, किताब, लाइट, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। उन्होंने कहा कि जहां सब कुछ है, वहां पढ़ाई में नकल हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरिद्वार में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मौजूदा शिक्षा व्यवस्था और सरकारी भर्ती प्रकियाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने बिजली, शिक्षकों की कमी, सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू में घोटाला समेत तमाम मुद्दों को उठाया।

योगगुरु बाबा रामदेव ने कहा कि

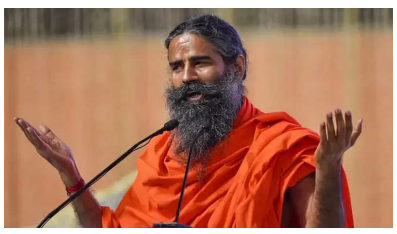

देश में चारों तरफ हंगामा है। बच्चे कह रहे कि हमारे यहां टीचर नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। उन्होंने कहा कि कहीं नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है तो कहीं सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू में 99% घोटाला होता है। उन्होंने चेतावानी देते हुए कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो आंदोलन और ज्यादा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में घपला भी बहुत है।

बाबा रामदेव ने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99 प्रतिशत तक घोटाला होता है। अपने जाति, वर्ग, समुदाय और विचार के लोगों को नौकरी देते हैं और बाकियों को धक्का मार देते हैं। उन्होंने कहा कि यह सब अपमानजनक और लोकतंत्र के खिलाफ है।

स्वामी रामदेव ने कहा कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। नहीं तो देश में और भी ज्यादा आंदोलन हो सकते हैं। उन्होंने कहा वैसे तो आंदोलन के नाम पर वह अराजकता का समर्थन और उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि देश में घपला भी बहुत है। उन्होंने कहा कि ये घपले ठीक कर लो, कहीं ऐसा न हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करने पड़े।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया ध्वजारोहण

संवाददाता

देहरादून। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया।

आज यहां 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रध्वज को सलामी दी तथा देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जनपदवासियों एवं कलेक्ट्रेट परिवार को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश को स्वतंत्रता बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। उनके त्याग, संघर्ष और बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में अपने दायित्वों का निर्वहन कर पा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता को बनाए रखना और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना हम सभी की बड़ी जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि हम सभी जिस भी पद पर कार्यरत हैं और जो दायित्व हमें सौंपे गए हैं, उनका पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवा का उद्देश्य आमजन की सेवा और जनहित में कार्य करना है। प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन करते हुए शासन की योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पुनः स्मरण कराने का अवसर देता है। हमें स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देना चाहिए। उन्होंने सभी से अपने कार्यक्षेत्र में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में देशभक्ति एवं राष्ट्रप्रेम का माहौल रहा। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए राष्ट्रहित में कार्य करने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार, नगर मजिस्ट्रेट राकेश तिवारी, उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह, मुख्य वैयक्तिक अधिकारी जिलाधिकारी वीरेंद्र सिंह सहित कलेक्ट्रेट के अधिकारी एवं कर्मचारी, कलेक्ट्रेट प्रेस के कार्मिक तथा जिला सूचना कार्यालय के कार्मिक उपस्थित रहे।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।